



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 419]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

गृह मंत्रालय

(सी.एस. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

**सा.का.नि. 518(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कैदियों का संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि, उक्त अधिनियम के उपबंध कज़ाकिस्तान पर लागू होंगे। दण्डादेशित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और कज़ाकिस्तान की सरकार द्वारा दिनांक 08.07.2015 को हस्ताक्षरित करार का सम्पूर्ण पाठ नीचे दिया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2015 को और कज़ाकिस्तान की सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2016 को इस करार का अनुसमर्थन किया गया।

**दण्डादेशित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य तथा कज़ाकिस्तान गणराज्य के बीच संधि**

भारत-गणराज्य तथा कज़ाकिस्तान गणराज्य (जिन्हें इसमें इसके बाद “संविदाकारी देश” कहा गया है);

दण्डादेशित व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को उनके स्वयं के देशों में सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

इस बात पर गौर करते हुए कि यह उद्देश्य कोई दाण्डिक अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दण्डादेशित विदेशी नागरिकों को अपनी सजा अपने स्वयं के देश में काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं

**अनुच्छेद 1- परिभाषाएं**

(क) “निर्णय” से किसी न्यायालय या अधिकरण का ऐसा निर्णय या आदेश अभिप्रेत है जिसमें सज़ा अधिरोपित की गई हो;

(ख) “प्राप्तकर्ता देश” से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें दण्डादेशित व्यक्ति को सजा अथवा उसके शेष भाग को काटने के लिए अंतरित किया जा सकता है अथवा अंतरित कर दिया गया हो;

- (ग) “दण्ड” से अंतिम न्यायालय का ऐसा निर्णय अभिप्रेत है, जिसमें किसी अपराध को करने के लिए किसी निर्धारित अवधि के कारावास अथवा आजीवन कारावास की सजा दी गई हो;
- (घ) “दण्डादेशित व्यक्ति” से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संविदाकारी देश में किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत कारावास की सजा काट रहा हो;
- (ङ.) “अंतरणकर्ता देश” से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें अंतरित किए जा सकने वाले अथवा अंतरित किए जा चुके व्यक्ति को दण्ड दिया गया हो;

### अनुच्छेद 2-सामान्य सिद्धांत

- (1) एक संविदाकारी देश के भू-भाग में दण्डादेशित किसी व्यक्ति को इस करार के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है, ताकि वह अधिरोपित सजा को काट सके। इस उद्देश्य के लिए, वह, इस करार के अंतर्गत अंतरित किए जाने के लिए अपनी इच्छा अंतरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश को व्यक्त कर सकता/सकती है।
- (2) अंतरण के लिए अनुरोध, किसी दण्डादेशित व्यक्ति द्वारा, जो संविदाकारी देश का राष्ट्रिक हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो संविदाकारी देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए हकदार हो, संविदाकारी देश को आवेदन देकर तथा उस संविदाकारी देश के कानूनों द्वारा विहित तरीके से किया जा सकता है।

### अनुच्छेद 3-केन्द्रीय प्राधिकरण

1. इस करार के कार्यान्वयन के प्रभारी केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे;
  - भारत गणराज्य के लिए: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
  - कज़ाकिस्तान गणराज्य के लिए: कज़ाकिस्तान के महा अभियोजक का कार्यालय।
2. यदि कोई भी संविदाकारी देश अपना केन्द्रीय प्राधिकरण बदलता है तो, वह दूसरे देश को राजनयिक चैनलों के माध्यम से इसके बारे में अधिसूचित करेगा।

### अनुच्छेद 4-अंतरण की शर्तें

1. इस करार के अंतर्गत किसी दण्डादेशित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है :
  - (क) व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का राष्ट्रिक हो;
  - (ख) दण्डादेशित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया हो;
  - (ग) निर्णय अंतिम हो;
  - (घ) अंतरणकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक या अन्य कार्यवाहियां लंबित नहीं हों जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो;
  - (ङ.) दण्डादेशित व्यक्ति को किसी सैन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो;
  - (च) अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने के समय, दण्डादेशित व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए अभी भी कम-से कम छह माह शेष हो या वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो;
  - (छ) ऐसे कार्य या लोप, जिनके लिए उस व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में दण्डादेशित किया गया था, वे हैं, जो प्राप्तकर्ता देश में एक अपराध के रूप में दंडनीय है, या वे दांडिक अपराध होते यदि उसके भू-भाग में किए जाते;
  - (ज) प्राप्तकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति के अंतरण एवं अभिरक्षा से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा अन्य किसी हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  - (झ) अंतरण के लिए सहमति, दण्डादेशित व्यक्ति द्वारा या जहां उसकी उम्र अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को देखते हुए दोनों में से कोई संविदाकारी देश आवश्यक समझे तो, किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा या

संविदाकारी देश के कानून के अनुसार दण्डादेशित व्यक्ति की ओर से कार्रवाई करने के लिए पात्र अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दी जाए; तथा

(ज) अंतरणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता देश अंतरण के लिए सहमत हों;

2. आपवादिक मामलों में, अंतरणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता देश अंतरण के लिए सहमत हो सकते हैं चाहे दण्डादेशित व्यक्ति द्वारा काटी जाने वाली सज़ा की शेष रह गई अवधि छह माह से कम हो।

#### अनुच्छेद-5 सूचना प्रदान करने का दायित्व

1. यदि दण्डादेशित व्यक्ति ने इस करार के अंतर्गत अंतरणकर्ता देश के सामने रुचि व्यक्त की है तो अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा जब तक कि प्राप्तकर्ता देश या अंतरणकर्ता देश ने यह पहले ही निर्णय नहीं ले लिया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं होगा:

(क) दण्डादेशित व्यक्ति का नाम एवं उपनाम एवं राष्ट्रीयता, जन्मतिथि और जन्म स्थान तथा प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो, और साथ ही उसके पासपोर्ट या किसी अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रति और दण्डादेशित व्यक्ति का यथा संभव फिंगरप्रिंट;

(ख) उन तथ्यों का विवरण जिस पर दंड आधारित था;

(ग) दंड की प्रकृति, अवधि और उसके प्रारंभ होने की तारीख;

(घ) निर्णय की एक प्रमाणित प्रति तथा कानून के संगत उपबंधों की एक प्रति जिसके अंतर्गत दण्डादेशित व्यक्ति के विरुद्ध सजा पारित की गई है;

(ङ) दण्डादेशित व्यक्ति के पूर्ववृत्तों और चरित्र के बारे में चिकित्सीय, सामाजिक या कोई अन्य रिपोर्ट, जहां यह उसके आवेदन के निपटान के लिए या उसको बंदी बनाए जाने की प्रकृति के बारे में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त हो;

(च) कोई अन्य सूचना जो प्राप्तकर्ता देश सभी मामलों में अपेक्षित को विनिर्दिष्ट करे ताकि वह अंतरण की संभावना पर विचार कर सके और अपने कानून के अंतर्गत उसके लिए अंतरण के सभी परिणामों के बारे में दण्डादेशित व्यक्ति को सूचित किया जा सके;

(छ) अंतरित किए जाने वाले दण्डादेशित व्यक्ति या अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी व्यक्ति के अनुरोध से संबंधित विवरण;

(ज) एक विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दंड की कितनी अवधि को पहले ही काट लिया गया है और साथ ही जिसमें किसी विचारण पूर्व निरोध, दंड की माफी या दंड के प्रवर्तन से संगत किसी अन्य तथ्य से संबंधित सूचना हो;

2. इस करार के अंतर्गत अनुरोध पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए, प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा जब तक कि प्राप्तकर्ता देश या अंतरणकर्ता देश ने यह पहले ही निर्णय नहीं ले लिया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं होगा;

(क) एक विवरण, या दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दण्डादेशित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का राष्ट्रिक है;

(ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति, जिसमें यह उपबंध किया गया हो कि ऐसे कार्य या लोप, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दंड अधिरोपित किया गया है, प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार एक दाण्डिक अपराध है, या वे दाण्डिक अपराध होते यदि उसके भू-भाग पर किए गए होते;

(ग) दण्डादेशित व्यक्ति के अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 10 के पैरा 1 (ग) के प्रभाव से संबंधित एक विवरण, यदि लागू हो, सहित उसके अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में दंड की अवधि एवं प्रवर्तन से संबंधित किसी कानून या विनियम के प्रभाव का विवरण;

- (घ) दण्डादेशित व्यक्ति का अंतरण स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की इच्छा तथा दण्डादेशित व्यक्ति के दंड के शेष हिस्से को प्रशासित करने की वचनबद्धता; तथा
- (ङ) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जो अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

#### अनुच्छेद 6-अनुरोध और उत्तर

1. अंतरण के लिए अनुरोध विहित प्रपत्र, यदि कोई हो, में लिखित में किया जाएगा, तथा अंतरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्राप्तकर्ता देश को भेजा जाएगा। उत्तर उन्हीं चैनलों के माध्यम से दिए जाएंगे।
2. प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश को अपने इस निर्णय के बारे में तुरंत सूचित करेगा कि वह निवेदित अंतरण से सहमत है या नहीं।

#### अनुच्छेद 7- सहमति एवं इसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा, कि इस करार के अनुच्छेद 4 के पैरा 1(i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति अंतरण के कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ स्वेच्छा से अंतरण की सहमति देगा। ऐसी सहमति, यदि दी जाती है, तो उसे देने के लिए प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित होगी।
2. अंतरणकर्ता देश, यह सत्यापित करने के लिए प्राप्तकर्ता देश को एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति इस अनुरोध के पैरा 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है।

#### अनुच्छेद 8-प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

- (1) प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय या प्रशासनिक आदेश के माध्यम से दंड का प्रवर्तन जारी रखेंगे, जो इस करार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत उनके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित हों।
- (2) इस करार के अनुच्छेद 11 के उपबंधों के अधीन, दंड का प्रवर्तन, प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित होगा और वह देश अकेला ही सभी उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

#### अनुच्छेद 9- दण्डादेशित व्यक्तियों को सौंपा जाना

अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को अंतरित व्यक्ति को ऐसे स्थान पर सौंपेगा, जिसके बारे में अंतरणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता देश, के बीच सहमति होगी। प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश से कैदी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होगा और, वह अंतरणकर्ता देश के भू-भाग के बाहर दण्डादेशित व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा।

#### अनुच्छेद 10-दंड का सतत प्रवर्तन

दण्डादेशित व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद, प्राप्तकर्ता देश निम्नलिखित का अनुपालन करेगा:

- (क) दंड के कार्यान्वयन का तौर-तरीका एवं प्रक्रियाएं उसके यहां लागू राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार होंगी;
- (ख) दंड का कार्यान्वयन, उसकी अवधि या प्रकृति में संशोधन किए बिना, निर्णय में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, दंड को बढ़ाया नहीं जाएगा;
- (ग) यदि प्राप्तकर्ता देश के राष्ट्रीय विधान में दंड के लिए अधिकतम अवधि का प्रावधान है, जो अंतरणकर्ता देश द्वारा प्रदान की गई अवधि से कम है, तो प्राप्तकर्ता देश उसी अपराध के लिए अपने राष्ट्रीय विधान में उपबंधित अधिकतम अवधि का अनुपालन करेगा। ऐसे अनुकूलन की दशा में, प्राप्तकर्ता देश अनुकूलन संबंधी कानूनी दस्तावेज की एक प्रति तत्काल अंतरणकर्ता देश को प्रेषित करेगा;
- (घ) दण्डादेशित व्यक्ति द्वारा अंतरणकर्ता देश के भू-भाग के भीतर सजा की समयावधि कम की जाएगी;
- (ङ) प्राप्तकर्ता देश किसी वित्तीय शास्ति (अपराध का शमन करने) के लिए कारावास को प्रतिस्थापित नहीं करने का वचन देगा।

**अनुच्छेद 11-अंतरणकर्ता देश के लिए दण्ड को पूरा किए जाने का प्रभाव**

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैरा 1 (क) के अंतर्गत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि उक्त दण्ड पूरा कर लिया गया है तो इस प्रकार की अधिसूचना का आशय यह होगा कि अंतरणकर्ता देश में उस दण्ड को पूरा कर लिया गया है।

**अनुच्छेद 12-निर्णय तथा माफी, राजक्षमा अथवा दण्ड को कम किए जाने की समीक्षा**

1. निर्णय की समीक्षा अथवा किसी आवेदन पर निर्णय केवल अंतरणकर्ता देश ही लेगा।
2. दोनों संविदाकारी देशों में से कोई एक संविदाकारी देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुसार दण्ड को माफ कर सकता है, क्षमादान दे सकता है अथवा दण्ड को कम कर सकता है।

**अनुच्छेद 13- दंड के प्रवर्तन का समापन**

1. अंतरणकर्ता देश अपने भू-भाग में लिए गए किसी निर्णय, जिसके लिए सजा या उसके हिस्से के प्रवर्तन का समापन आवश्यक हो, के बारे में तुरंत प्राप्तकर्ता देश को अधिसूचित करेगा।
2. जैसे ही प्राप्तकर्ता देश को अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी ऐसे निर्णय या उपाय के बारे में सूचित किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप सजा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, प्राप्तकर्ता देश सजा या उसके हिस्से के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

**अनुच्छेद 14-नॉन बिस इन आइडेम**

अंतरण के बाद, दण्डादेशित व्यक्ति को उन्हीं दांडिक कृत्यों, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में सजा अधिरोपित की गई थी, के लिए प्राप्तकर्ता देश में अभियोजित नहीं किया जाएगा या उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**अनुच्छेद 15-दण्ड के प्रवर्तन के बारे में सूचना**

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को तब सूचना देगा:
  - (क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; या
  - (ख) दण्ड का प्रवर्तन पूरा हो जाने से पूर्व दण्डादेशित व्यक्ति हिरासत से भाग निकला हो। ऐसे मामलों में, प्राप्तकर्ता देश उसके द्वारा सजा की शेष अवधि को काटे जाने के प्रयोजन से और उसे अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए प्राप्तकर्ता देश अपने संगत कानून के अंतर्गत उपाय करेगा।
  - (ग) दंड पूरा करने से पहले दण्डादेशित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में।
2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा यह अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**अनुच्छेद 16-पारगमन**

1. यदि दोनों में से कोई संविदाकारी देश दण्डादेशित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकारी देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से होकर अंतरित किए जा रहे दण्डादेशित व्यक्तियों के पारगमन को सुगम बनाने में सहायता करेगा, सिवाय इसके कि वह पारगमन प्रदान करने से मना कर दे।

(क) यदि दण्डादेशित व्यक्ति उसके अपने नागरिकों में से एक हो।

(ख) यदि अनुरोध से संविदाकारी देश की संप्रभुता, सुरक्षा, जनादेश या किसी अन्य आवश्यक हित का अतिलंघन होता हो।

2. ऐसा अंतरण करने के इच्छुक संविदाकारी देश में दूसरे संविदाकार देश को ऐसे पारगमन के बारे में सूचना देगा।

**अनुच्छेद 17-लागत**

अंतरणकर्ता देश के भू-भाग में किए गए खर्चों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आई किन्हीं लागतों का वहन, पूरी तरह से प्राप्तकर्ता देश द्वारा किया जाएगा।

यदि प्राप्तकर्ता देश भारत है तो वह तथापि, अंतरण की पूरी या आंशिक लागतों की वसूली दण्डादेशित व्यक्ति से या किसी अन्य स्रोत से कर सकता है।

### अनुच्छेद 18-भाषाएं

इस संधि के प्रयोजन के लिए पक्षकार अपनी-अपनी राजभाषा का उपयोग करेंगे और दूसरे पक्षकार की राजभाषा में या अंग्रेजी में अनुवाद प्रदान करेगा।

### अनुच्छेद 19-लागू होने का कार्यक्षेत्र

यह करार, इस करार के लागू होने से पहले या बाद में अधिरोपित दंडों के प्रवर्तन पर लागू होगा।

### अनुच्छेद 20-विवादों का निपटान

1. केन्द्रीय प्राधिकारी, करार की व्याख्या, उसके लागू किए जाने, अथवा इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी विवाद का निपटान पारस्परिक रूप से करने का प्रयास करेंगे।
2. यदि केन्द्रीय प्राधिकारी पारस्परिक रूप से विवाद का निपटान नहीं कर पाते हैं तो इसको राजनयिक माध्यम से निपटाया जाएगा।

### अनुच्छेद-21 संशोधन

इस करार में संविदाकारी देशों की सहमति से कोई संशोधन या आशोधन उसी तरीके से लागू होंगे जिस तरीके से करार लागू हुआ था।

### अनुच्छेद 22-अंतिम उपबंध

1. यह करार अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगा। प्रत्येक संविदाकारी देश इस करार को लागू करने हेतु अपेक्षित अपनी विधिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, राजनयिक चैनलों के माध्यम से यथाशीघ्र दूसरे संविदाकारी देश को लिखित में अधिसूचित करेगा। यह करार पिछली अधिसूचना की तारीख के दूसरे माह के प्रथम दिन को लागू होगा।
2. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा। तथापि, दोनों में से कोई भी संविदाकारी देश राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे संविदाकारी देश को लिखित में नोटिस देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है। यह समापन, सूचना दिए जाने की तारीख से छः महीने बाद प्रभावी होगा।
3. किसी करार को समाप्त करने के बावजूद, यह ऐसे कैदियों के दंड के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिनको इस करार को समाप्त करने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया है।

इस करार के साक्ष्य के रूप में अपने-अपने "संविदाकारी देश" द्वारा इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किए जाने पर, अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसे अस्ताना में दिनांक 8 जुलाई, 2015 को हिन्दी, कज़ाक और अंग्रेजी भाषाओं, तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक भाषाओं में, दो-दो प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ह./-

भारत गणराज्य  
की ओर से

ह./-

कज़ाकिस्तान  
गणराज्य की ओर से

[फा. सं. V- 17011/01/2009-पी आर]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****(CS Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2017

**G.S.R. 518(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to Kazakhstan. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Kazakhstan on 08.07.2015 is given below. The Agreement was ratified by the Government of India on 09.10.2015 and by the Government of Kazakhstan on 04.03.2016.

**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Republic of India and the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the Contracting States);

**Desiring** to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

**Considering** that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own country ;

Have agreed as follows:

**Article 1-Definitions**

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “Receiving State” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve the sentence or remainder thereof;
- (c) “sentence” means any final court decision imposing a penalty of imprisonment for a determinate period of time or for life imprisonment for committing an offence;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a court in the Contracting States;
- (e) “Transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

**Article 2-General Principles**

(1) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement so as to serve the sentence imposed. To that end, he/she may express to the Transferring State or the Receiving State his/her willingness to be transferred under this Agreement.

(2) Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Laws of that Contracting State.

**Article 3-Central Authorities**

1. Central Authorities in charge of the implementation of this Agreement are;
  - For the Republic of India: Ministry of Home Affairs, Government of India.
  - For the Republic of Kazakhstan : General Prosecutor’s Office of Republic of Kazakhstan
2. In case either Contracting State changes its Central authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

**Article 4-Conditions for transfer**

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions-
  - (a) the person is a national of the Receiving State;
  - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
  - (c) the judgment is final;
  - (d) no criminal or other proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required.
  - (e) The Sentenced person has not been convicted for a military offence
  - (f) At the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
  - (g) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the Transferring State are those which are punishable as a crime in the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
  - (h) transfer and custody of the sentenced person to the Receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the Transferring State;
  - (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any legal representative or other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
  - (j) the Transferring and Receiving States agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the Transferring and Receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

**Article 5 -Obligation to furnish information**

1. If the sentenced person has expressed an interest to the Transferring State under this Agreement, the Transferring State shall send the following information and documents to the Receiving State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
  - (a) the name and surname and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the Receiving State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and Fingerprints of the Sentenced Person as possible;
  - (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
  - (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
  - (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
  - (e) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
  - (f) any other information which the Receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
  - (g) the statement related to request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Transferring State;
  - (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission of punishment, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.



2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or certified copy of document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving State;
- (b) a copy of the relevant law of the Receiving State which provides that the acts or omissions, on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory.
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 1 (c) of Article 10 of this Agreement on his transfer;
- (d) the willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) Any other information or document which the Transferring State may consider necessary.

#### **Article 6-Requests and replies**

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed by central authority of the Transferring State through diplomatic channels to the central authority of the Receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. The Receiving State shall promptly inform the Transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

#### **Article 7 -Consent and its verification**

1. The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent, if provided, shall be governed by the law of the Transferring State.

2. The Transferring State shall afford an opportunity to the Receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

#### **Article 8 -Effect of transfer for the Receiving State**

1. The competent authorities of the Receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

#### **Article 9- Handing over of sentenced persons**

The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving State. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the Transferring State.

#### **Article 10-Continued enforcement of sentence**

Upon receiving the sentenced person, the Receiving State shall observe the following:

- (a) Manner and procedures of execution of the sentence shall be in accordance with its applicable national laws;
- (b) Execution of the sentence shall be as provided for in the judgment, without amendment to its term or nature. In any event, the sentence may not be aggravated;

- (c) If national legislations of the Receiving State provide for a maximum term for the punishment which is less than the term rendered by the Transferring State, the Receiving State shall adhere to the maximum term provided in its national legislations for the same offence. In case of such adaptation, the Receiving State shall promptly transmit a copy of the legal document on the adaptation to the Transferring State;
- (d) The period of time served within the territory of the Transferring State by the sentenced person shall be deducted;
- (e) The Receiving State undertakes not to substitute an imprisonment for a financial penalty (Compounding the offence).

#### **Article 11- Effect of completion of sentence for the Transferring State**

When the Receiving State notifies the Transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the Transferring State.

#### **Article 12- Review of Judgment and Pardon, amnesty or communication**

1. The Transferring State alone shall decide on the review of the judgment or any application.
2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

#### **Article 13- Termination of enforcement of sentence.**

1. The Transferring State shall promptly notify the Receiving State of any decision taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

#### **Article 14- Non bis in idem**

After transfer, the sentenced person shall not be prosecuted or proceeded against in Receiving State for the same criminal acts as the ones on account of which the sentence was imposed in the Transferring State.

#### **Article 15 -Information on enforcement of sentence**

1. The Receiving State shall notify the Transferring State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) if the sentenced persons escape from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the Receiving State shall take measure to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/her liable for committing an offence under the relevant law of the Receiving State.
- (c) In case of death of the sentenced person before the completion of the sentence
2. The Receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the Transferring State

#### **Article 16-Transit**

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit
  - (a) if the sentenced person is one of its own nationals.
  - (b) If the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit

**Article 17- Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the Receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the Transferring State.

In case the Receiving State is India it may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source

**Article 18-Languages**

For purposes of this Agreement, the Parties shall use their respective official languages and provide a translation into the official language of the other Party or into English.

**Article 19- Scope of Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

**Article 20- Settlement of Disputes**

1. The Central Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
2. If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

**Article 21-Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into force in same manner as the Agreement itself.

**Article 22- Final Provisions**

1. This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.
2. The Agreement remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoners who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

**In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.**

**Done in Astana on the 8<sup>th</sup> day of July 2015 in duplicate each in Hindi, Kazakh and English languages, the three texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement the English text shall prevail.**

Sd/-

**For the Republic of India**

Sd/-

**For the Republic of Kazakhstan**

[F. No. V-17011/01/2009-PR]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.